टाइटल कोड - MPHIN7675
Email- haldharkisankgn@gmail.com

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

प्रधान संपादक - विवेक जैन

वर्ष 01 अंक 06 | अगस्त 2022 | पृष्ठ-8 मूल्य -5.00 रुपये

जलवायु परिवर्तन पर सांसदों ने महज 0.3 फीसदी प्रश्न पूछे

बीते 20 सालों में जहां जोखिम ज्यादा वहां के सवाल भी कम

भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है लेकिन जलवायु परिवर्तन के जोखिम के मामले में भी दुनिया में 191 देशों में 29वें स्थान पर है। इसके बावजूद बीते 20 वर्षों में यानी 1999-2019 के बीच संसद में 895 बार 1019 सदस्यों द्वारा जलवायु परिवर्तन पर सवाल पूछे गए हैं। यह संसद में इन 20 वर्ष की अवधि में कुल पूछे गए सवालों का महज 0.3 फीसदी है।

हलधर किसान। सबसे दिचलस्प यह है कि संसद में जलवायु परिवर्तन से जुड़े सर्वाधिक सवाल कुछ चुनिंदा वर्षों में पूछे गए। यानी जिस वर्ष जलवायु परिवर्तन से जुड़े कोई निर्णय, नीति या फैसला लिया गया। 2006 में जहां 8 सवाल पूछे गए थे वहींए 2007 में 53 सवाल जलवायु परिवर्तन पर पूछे गए थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि 2007 में जलवायु परिवर्तन को लेकर राष्ट्रीय कार्ययोजना जारी की गई थी। इसके अलावा सर्वाधिक 104 सवाल 2015 में पूछे गए थे। इस वर्ष केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के काम का विस्तार करते हुए उसके नाम को बदलकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किया गया।

किस तरह के सवाल सांसदों ने पूछे हैं

इस मुद्दे पर अध्ययन बताता है कि 27.6 फीसदी सवाल जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर, 23.5 फीसदी पलायन पर पूछे गए हैं। जलवायु परिवर्तन पर अनुकूलन को लेकर सबसे कम 3.9 फीसदी सवाल पूछे गए हैं, जबकि भारत में इस विषय पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा ज्यादातर सवाल जलवायु परिवर्तन के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पूछे गए हैं। भारत में कृषि क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 17 फीसदी है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन के तटीय क्षेत्रों में प्रभाव और स्वास्थ्य पर पड़े वाले प्रभाव के बारे में पूछा गया है। जलवायु परिवर्तन से जड़े अन्य मुद्दों को बहुत ही कम या न के बराबर संसद में पूछा गया है।

यह नतीजे बंग्लुरू में स्थित अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनिबिलिटी विभाग की सीमा मुंडोली, जुबिन जैकब, रंजिनी मुरली और हरिनी नागेंद्र के साथ यूएस, के स्नो लेपर्ड ट्रस्ट ने इस मुद्दे पर क्लाइमेट चेंज द मिसिंग डिस्कोर्स इन द इंडियन पार्लियामेंट नामक अध्ययन में प्रकाशित किया है। यह शोधपत्र एनवॉयरमेंटल रिसर्च.क्लाइमेट में प्रकाशित किया गया है।

ऐसा माना जाता है कि जिन राज्यों पर जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक जोखिम है वहां के सांसद सदन में संसदीय सवालों के जरिए ज्यादा आवाज उठाएंगे लेकिन शोधार्थियों को ऐसा नहीं दिखा। यह भी माना जाता है कि महिला सांसदों को इस बारे में और ज्यादा आवाज उठानी चाहिए क्योंकि उनके ऊपर जलवायु परिवर्तन का और भी ज्यादा दुषप्रभाव पड़ेगा, लेकिन महिला सांसदों ने भी बहुत कम सवाल उठाए क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व बेहद कम है। अध्ययन में कहा गया है कि बीते 20 वर्षों में चरम मौसमी घटनाओं में काफी बढोत्तरी हुई है लेकिन इसकी तुलना में संसदीय सवालों में कोई बढत नहीं देखी गई। सिर्फछह सवाल ऐसे किए गए जो कि सामाजिक.आर्थिक कमजोर वर्ग और जलवायु न्याय से जुड़े हुए थे।

सांसद जलवायु परिवर्तन से जुड़े सवालों का जवाब कहां से हासिल करते हैं, इस पर अध्ययन बताता है कि वे केवल 10 फीसदी संसदीय सवालों के जवाब को अपनी जानकारी का स्रोत बनाते हैं। इसके अलावा 58.9 फीसदी अन्य शोध पत्रों, समाचार पत्र के आर्टिकल (22 फीसदी) कान्फ्रेंस से 11 फीसदी, संस्थानों से 5.6 फीसदी और अंतरराष्ट्रीय करारों से 1.1 फीसदी जानकारी जुटाते हैं।

शेष पेज 3 पर...

केंद्रीय भूजल बोर्ड के वैज्ञानिक ने अध्ययन में किया खुलासा

खरगोन में भू-जल की स्थिति चिंताजनक, शेष 8 जनपद बेहतर

हलधर किसान (विवेक जैन)। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भू-जल की वर्तमान स्थिति पर केंद्रीय भूजल बोर्ड भोपाल के अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार कि है, जिसमें 9 जनपदों वाले खरगोन जिला मुख्यालय कि स्थिति चिंताजनक जबकि शेष 8 जनपदों की स्थिति बेहतर बताई गई है। रिपोर्ट को कलेक्टर सभाकक्ष में हुई बैठक के दौरान अफसरों से साझा कर प्रस्तुतिकरण किया। इस बैठक में वैज्ञानिकों ने बताया कि जिले में अंडर ग्राउंड वॉटर की अब वास्तविक स्थिति क्या है? हम भूमि की तह में स्टोर हुए कितने जल का उपयोग घरेलू कार्य और सिंचाई के लिए दोहन कर चुके है।

हालिया स्थिति के रूप में वैज्ञानिकों ने बताया कि जिले में खरगोन जनपद की स्थिति सेमिक्रिटिकल की ओर पहुँच चुकी है। अगर प्रतिशत के तौर पर देखे तो यहां 76.53 प्रतिशत भूजल विकास की दर पायी गई है। जिससे जनपद सेमिक्रिटिकल स्टेज में आ गया है। जबकि जिले के अन्य जनपद अभी सुरक्षित स्थिति में है। प्रस्तुतिकरण करने वाले वैज्ञानिक लता उद्सैय्या और रोज अनिता कुजूर ने प्रशासन के साथ जिले में अंडर ग्राउंड वॉटर की ताजा उपलब्धता की स्थिति साझा की है। बैठक में अपर कलेक्टर केके मालवीय, अतिरिक्त सीईओ पुरुषोत्तम पाटीदार, जलसंसाधन के कार्यपालन यंत्री पीके ब्राम्हणे, परियोजना अधिकारी एसके रघुवंशी, पीएचई कार्यपालन यंत्री मंजू सिंह, एनवीडीए के कार्यपालन यंत्री जेएस राणावत, टीआर पंचारे आदि उपस्थित रहे।

ये सुझाये उपाय

प्रस्तुत की गई प्रबंधन योजना में जल की मांग एवं आपूर्ति शामिल रही। वैज्ञानिकों ने कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं बताई गई है। जिसमे स्टॉप डेम, परकोलेशन टैंक, कंटूर ट्रेंच, अमृत सरोवर, रिचार्ज शॉप्ट और रिचार्ज ट्रेंच प्रस्तुत किये गए। इन संरचनाओं के निर्माण के बाद 187 मिलियन क्यूबिक मीटर तक भूजल बढ़ने की सम्भावना बताई गई है। तब भी सिंचाई के लिए जल का उपयोग स्प्रिंक्लर और ड्रिप सिंचाई से करने की सलाह दी गई है। इसी तरह जल की गुणवत्ता के लिए वैज्ञानिकों ने रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरक उपयोग करने की सलाह दी गई है।

जिले के जल में 62 प्रतिशत नाइट्रेट की मात्रा

वैज्ञानिकों द्वारा साझा किए गए मानचित्र, विशेषताएं, मुद्दे और जल प्रबंधन की योजना में आया कि जिले में अंदर ग्राउंड वॉटर के लिए गए नमूनों में 62 प्रतिशत नमूनों में नाइट्रेट की मात्रा अनुमानित सीमा से अधिक पायी गई है। इससे बच्चों में ब्लू बेबी बीमारी होने की सम्भावना रहती है। इसमें बच्चों की त्वचा ब्लू हो सकती है।

घरेलू और सिंचाई में इतना हुआ दोहन

वैज्ञानिकों द्वारा साझा किए गए प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि सिंचाई के मामले में सेगांव जनपद में 3171.068 और घरेलू जल के लिए 217.4736 प्रति हेक्टेयर मीटर जल का दोहन हुआ है। इसी तरह बड़वाह जनपद में सिंचाई में 6991.86 और घरेलू में 735.2776 हेक्टेयर मीटर, भीकनगांव में सिंचाई में 6353.11 और घरेलू में 491.6577 हे. मी, कसरावद में सिचांई में 5446.45 और घरेलू में 575.8769 हेमी, खरगोन में 4357.6416 और घरेलू में 356.6196 हे.मी, भगवानपुरा में सिंचाई के लिए 2218.17 और घरेलू के लिए 536.3617 हे.मी, गोगांवा में सिंचाई के लिए 3070.02 और घरेलु के लिए 292.2314 हेमी महेश्वर में सिंचाई के लिए 5958.61 और घरेलू के लिए 515.4091 हे.मी तथा झिरन्या जनपद में सिंचाई के लिए 3866.9032 और घरेलू के लिए 572.5974 हेमी जल का दोहन हो चुका है। इस तरह पूरे जिले में सिंचाई में 41433.83 और घरेलू के लिए 4293.5 हेमी जल का दोहन हुआ है। जबकि जिले में भविष्य के लिए अंडर ग्राउंड में जल की कुल उपलब्धता 59783.75 हे.मी है।

धरती की प्यास...

धरती की प्यास और किसान की आस, कभी खत्म नहीं होती और प्रकृति ने भी निराश नहीं किया। प्रदेशभर में अच्छी बारिश के चलते किसानों के चेहरों पर रौनक देखने को मिल रही है। इसके चलते किसानों को अ ब उम्मीद है कि इस बार उनकी उपज भी अच्छी ही होगी

मयंक अत्रे

और मौसम भी उनका साथ देगा। पिछले साल मौसम की मार के कारण कई जगह अधिक तो कुछ जगहों पर कम बारिश से फसलों को नुकसान हुआ। इसका उत्पादन पर भी असर रहा। लेकिन इन सब समस्याओं के बावजूद वो किसानो की आस ही रहती है जो किसानों और ज्यादा मेहनत के लिए प्रेरित करती है, और इस दुनिया का पेट भी इसी आस के बदौलत भरता है।

ब्राजील के सहयोग से हिसार में पशुओं की नस्ल सुधार के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा: मंत्री दलाल

हलधर किसान। हरियाणा के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हिसार में पशुओं की नस्ल सुधार के लिए उत्कृष्टता केंद्र ब्राजील के सहयोग से खोले जाने की तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा, पशुओं के आहार में प्रोटीन की मात्रा को बढाने के लिए कनाडा की कंपनी द्वारा एक सेंटर राज्य में खोला जाएगा जिसके तहत इस कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही हरियाणा का दौरा करेगा और उसके बाद एक समझौता ज्ञापन होगा।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन एवं डेयरिंग मंत्री जेपी दलाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान साझा की। ब्राजील दौरे के संबंध में बताया कि ब्राजील में वर्ष 1911 में भावनगर के राजा ने गिर नस्ल की गायों को दान के स्वरूप ब्राजील को दिया था

और उसके बाद ब्राजील ने इन गायों की नस्ल सुधार में काम किया गया। उन्होंने कहा कि ब्राजील में गिर गाय की नस्ल में सुधार कर गिरलैंडो नस्ल को तैयार किया गया है जो औसतन 15 लीटर दूध देती हैं जिसमें 99 प्रतिशत जेनेटिक्स हमारे देश की गिर गाय के पाए जाते हैं। गिर गाय की नस्ल सुधार की तर्ज पर देसी, हरयाणा, साहीवाल और राठी गाय की नस्लों में सुधार होगा।

प्रमुख बिंदु

- ब्राज़ीलियन एसोसिएशन ऑफजेबू ब्रीडर्स से गिर जर्मप्लाज़्म (वीर्य/ भ्रुण) का आयात किया जाएगा।
- ब्राज़ील की एक ज़ीनोमिक्स कंपनी एल्टा जेनेटिक्स को गुणवत्ता वाले मुर्राह जर्मप्लाज़्म के निर्यात की संभावनाएँ तलाशी जाएंगी।
-हरियाणा में कृषि क्षेत्र में व्यापार के अवसर तलाशने हेतु इंडो.ब्राज़ीलियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को निमंत्रण दिया गया है।

संपादकीय...

बाजार तक किसानों की पहुंच हो रही आसान, भविष्य के लिए सुखद संकेत

करीब एक साल तक जिन किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने की सरकार से गारंटी के लिए धरना.प्रदर्शन किया, वही आज अपनी उपज सरकारी एजेंसियों को न बेचकर खुले बाजार में एमएसपी से ऊंची कीमत पर निजी कारोबारियों को बेच रहे हैं। गेहूं ही नहीं सरसों, कपास, चना की बिक्री भी समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर हो रही है। सबसे बड़ी बात यह हुई कि अनाज की बिक्री के लिए पंजीकरण के बावजूद किसान अपनी उपज लेकर सरकारी खरीद केंद्रों पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि व्यापारी खुद उन तक जा रहे हैं। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है। इस साल 29 मई तक 17.5 लाख किसानों से 184.5 लाख टन गेहूं की खरीद की गई। यह खरीद 2021.22 की सरकारी खरीद 433.4 लाख टन से 53 प्रतिशत कम है। सरकार ने 2022.23 के लिए 444 लाख टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन निज ी कारोबारियों द्वारा 2.500 से 3.000 रुपये प्रति क्विंटल की आक्रामक खरीदारी के कारण किसान समर्थन मूल्य 2.015 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की बिक्री के लिए उत्साह नहीं दिखा रहे। जिन राज्यों में सरकारी खरीद का व्यवस्थित नेटवर्क नहीं है, वहां भी निजी एजेंसियां एमएसपी से ऊंची कीमत देकर गेहूं की खरीद कर रही हैं। यह भविष्य के लिए एक सुखद संकेत है।

विश्व के गेहूं कारोबार में 29 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले रूस.यूक्रेन के युद्धरत होने के चलते दुनिया में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इससे विश्व में गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं। इसी कारण भारत सरकार ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। भविष्य में गेहूं की ऊंची कीमत मिलने की उम्मीद में भी बहुत से किसान उपज नहीं बेच रहे हैं। आज किसानों को एमएसपी से अधिक कीमत मिल रही है तो इसका श्रेय आठ वर्षों में मोदी सरकार द्वारा किए गए विपणन सुधारों को जाता है। मोदी सरकार कृषि उपज की खरीद.बिक्री में सरकारी क्षेत्र के समानांतर निजी क्षेत्र की मौजूदगी बना रही है। इससे खरीद में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगीए जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। गेहूं, सरसों, कपास के मामले में तो यह लाभ मिलने भी लगा है। आगे अन्य फसलों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार परंपरागत मंडी व्यवस्था को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक व्यवस्था में बदल रही है, ताकि कृषि उपज के कारोबार में बाधा न आए। इसके तहत मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई.नाम) पोर्टल से जोड़ा जा रहा है, ताकि किसान सभी मंडियों में अपनी उपज का कारोबार कर सकें। 31 दिसंबर 2021 तक 18 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों की 1.000 मंडियों को ई.नाम प्लेटफार्म में बदला जा चुका है। इससे 1.72 करोड़ किसान और दो लाख ट्रेडर्स जुड़े हैं। अब 1.000 नई मंडियों को ई.नाम पोर्टल से जोड़ने का काम जारी है।

ई.नाम योजना को मिली सफलता को देखते हुए मोदी सरकार ग्रामीण हाटों को मिनी एपीएमसी मार्केट में बदल रही है। मनरेगा के तहत अब तक 1.351 ग्रामीण हाटों को बदला जा चुका है। 1.632 ग्रामीण हाटों को मिनी एपीएमसी मार्केट में बदलने की प्रक्रिया जारी है। 31 मार्च 2020 तक देश में 6.845 एपीएमसी बाजार थे। किसानों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने और बेहतर कीमत दिलाने के लिए उनका नियमन किया गया है। इनके अलावा देश भर में जो थोक बाजार खरीद केंद्र हैं, उन्हें भी सरकार विनियमित कर रही है। किसानों और बाजार के संबंध को मजबूत बनाने के लिए सरकार गोदाम और कोल्ड स्टोरेज को बाजार की मान्यता प्रदान करने जा रही है। उत्पादक केंद्रों को उपभोक्ता केंद्रों से जोड़ने के लिए सरकार किसान रेल चला रही है। इससे किसान दूरदराज के बाजारों में अपनी उपज बेच रहे हैं। इसके अलावा सरकार जल्द खराब होने वाले फलों.सब्जियों को उत्पादक केंद्रों से उपभोक्ता केंद्रों तक पहुंचाने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। पूवरेत्तर और हिमालयी राज्यों के शीघ्र खराब होने वाले फलों.सब्जियों की किसान उड़ान से ढुलाई के लिए भी सब्सिडी दे रही है। चूंकि छोटे किसानों की बाजार तक पहुंच सीमित होती है इसलिए सरकार किसान उत्पादक संगठन बना रही है। इसके तहत किसानों से फल, सब्जी, फूल, मछली आदि को खरीदकर सीधे कंपनियों को बेचा जाता है। इस व्यवस्था में किसानों का एक बड़ा समूह रहता है, इसलिए उनकी मोलभाव की ताकत बढ़ जाती है और उन्हें उपज की अच्छी कीमत मिलती है। सरकार ने 2024 तक दस हजार एफपीओ बनने का लक्ष्य तय किया है, जिससे 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके लिए 6.865 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

सरकार 'एक जिला एक उत्पाद' को कृषि क्षेत्र में लागू कर रही है। इसके तहत देश के सभी 773 जिलों में उनकी पारिस्थितिकी दशा के अनुरूप फसलों को चिह्नित किया गया है। इसमें बागवानी.औषधीय महत्व की फसलों को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि इनकी अच्छी कीमत मिलती है। इन्हीं उपजों के आधार पर हर जिले के पारंपरिक उद्योग को विकसित किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। देश में अब तक जितना ध्यान उत्पादन पर दिया गया, उतना उपज के भंडारण.विपणन पर नहीं। यही कारण है कि किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत नहीं मिल पा रही थी।

मोदी सरकार चुनिंदा फसलों के बजाय विविधीकृत फसलों के उत्पादन के साथ.साथ उनके भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन का देशव्यापी व्यवस्थित नेटवर्क बना रही है। इसी कारण अब किसानों को उनकी उपज की वाजिब कीमत मिलने लगी है।

प्रतियां पाने, लेख प्रकाशन के लिए संपर्क करें

हलधर किसान, राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र की प्रतिया प्राप्त करने के लिए अपना नाम, डाक पता और फोन नंबर सहित संपर्क करें। साथ ही कृषि, पशुपालन, बागवानी, अनुसंधान जैसे क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, शोध, खेती में नवाचार जैसे लेख प्रकाशन कराना चाहते है तो हमें वाट्सएप नंबर- 8305103633, 94254 89337 पर भेजे सकते है। हम आपका लेख प्रमुखता से फोटो सहित उचित स्थान पर प्रकाशित करेंगे।

गर्मी-सूखा और कीड़े जैसे तनावों का सामना करने के लिए पौधे खुद के लिए बनाते हैं एस्पिरिन

हलधन किसान। क्या आप जानते हैं कि गर्मी, सूखा और कीड़े जैसे खतरों से बचने के लिए पौधे सैलिसिलिक एसिड का उत्पादन करते हैं, जिसे एस्पिरिन भी कहा जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस बारे में बेहतर समझ पौधों को जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तनाव से सुरक्षित रखने में मददगार हो सकती है। इस संबंध में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, रिवरसाइड द्वारा की गई यह रिसर्च जर्नल साइंस एडवांसेज में प्रकाशित हुई है। इस रिसर्च में शोधकर्ताओं ने जानकारी दी है कि कैसे पौधे सैलिसिलिक एसिड के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं।

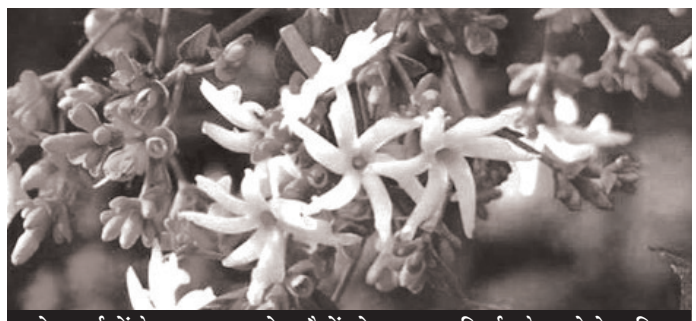

शोधकर्ताओं के अनुसार यह खोज पौधों को जलवायु परिवर्तन के खतरे से सुरक्षित रखने में मददगार हो सकती है।

गौरतलब है कि अपनी इस रिसर्च में शोधकर्ताओं ने अरबीडॉप्सिस नामक पौधे पर अध्ययन किया है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि इस पौधे की कोशिकाओं में तनाव प्रतिक्रियाओं के बारे में उन्होंने जो जानकारी हासिल की है उसे भोजन के लिए उगाए जाने वाले पौधों पर भी लागू किया जा सकता है। इस बारे में यूसीआर में प्लांट जेनेटिसिस्ट और अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता जिन.झेंग वांग का कहना है किए हम प्राप्त जानकारी का उपयोग फसलों में खतरों के प्रति प्रतिरोध में सुधार के लिए करना चाहते हैं। जो तेजी से गर्म होती दुनिया में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पर्यावरण सम्बन्धी तनावों के कारण सभी जीवों में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या आरओएस का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए धूप के समय यदि सनस्क्रीन न लगाएं तो इंसानी त्वचा आरओएस उत्पन्न करती है। जो झाईयों और जलन का कारण बनता है। हालांकि पौधों में आरओएस का उच्च स्तर घातक हो सकता है।

क्या है पौधे के सुरक्षा तंत्र का विज्ञान

कई अन्य पदार्थों की तरह ही यदि जहर भी एक निश्चित मात्रा में हो तो वो दवा का काम करता है। ऐसे है कम मात्रा में पादप कोशिकाओं में मौजूद आरओएस भी महत्वपूर्ण काम करता है। इस बारे में वांग ने बताया कि गैर घातक स्तर पर यह आरओएस पौधों के लिए एमर्जेन्सी कॉल की तरह होता हैए जो खतरे की स्थिति में पौधों में सैलिसिलिक एसिड जैसे सुरक्षात्मक हार्मोन के उत्पादन को प्रेरित करता है। शोधकर्ताओं के अनुसार गर्मी, धूप और सूखे की स्थिति में पौधों की कोशिकाएं में मौजूद शुगर उत्पन्न करने वाला सिस्टम एक शुरुआती अलार्म देने वाला मॉलिक्यूल पैदा करता है, जिसे एमईसीपीपी के रुप में जाना जाता है।

शोधकर्ता इस मॉलिक्यूल के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी की यह अणु बैक्टीरिया और मलेरिया परजीवी जैसे जीवों में भी उत्पन्न होता है। वहीं पौधों में इस अणु 'एमईसीपीपी' के जमा होने से वो सैलिसिलिक एसिड के उत्पादन को ट्रिगर करता है, जो बदले में पादप कोशिकाओं में सुरक्षा प्रक्रिया की एक पूरी शृंखला को शुरू कर देता है।

इस बारे में यूसीआर प्लांट बायोलॉजिस्ट और अध्ययन से जुड़े अन्य शोधकर्ता विल्हेल्मिना वैन डे वेन का कहना है किए यह ऐसा ही है जैसे पौधे दर्द के लिए दर्द निवारक दवा का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एसिड पौधों के क्लोरोप्लास्ट की रक्षा करता है, जो प्रकाश संश्लेषण में मददगार होता है। गौरतलब है कि प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा प्रकाश की मदद से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जो ऊर्जा पैदा करती है।

वैज्ञानिकों के अनुसार सैलिसिलिक एसिड पौधों को जलवायु परिवर्तन, सूखा, कीड़ों के साथ.साथ अन्य तनावों का सामना करने में मददगार होता है। साथ ही इसकी वजह से पौधे तनाव की स्थिति में भी उत्पादन बरकरार रख पाते हैं। देखा जाए तो यह मुद्दा सिर्फ खाद्य उत्पादन से ही जुड़ा नहीं है। इसके प्रभाव उससे कहीं ज्यादा हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर हमारी हवा को साफकरते हैं। वो हमें छाया प्रदान करने के साथ.साथ कई जानवरों को आवास प्रदान करते हैं। ऐसे में इनके अस्तित्व की रक्षा कहीं ज्यादा मायने रखती है।

पेज 1 का शेष....

जलवायु के परिवर्तन....

अध्ययन ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि जलवायु परिवर्तन की जिस स्तर की समस्या है उस अनुपात में संसद में बहुत कम सवालों का प्रतिनिधित्व है। वहीं प्रभावित राज्यों से सवाल बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं जबकि एडॉप्टेशन को लेकर चिंताएं भी बहुत कम नजर आती हैं।

जलवायु परिवर्तन पर किए गए एक नए अध्ययन के अनुसार, इस सदी के अंत तक उत्तरी गोलार्ध में अधिक बर्फवाले इलाकों के जल संसाधनों में तेजी से उतार.चढ़ाव होगा। साथ ही जल संसाधनों के बारे में पूर्वानुमान लगाना अधिक कठिन हो जाएगा। शोधकर्ताओं ने पाया कि उन इलाकों में भीए जहां समान मात्रा में बारिश हो रही है, वहां प्रवाह अधिक परिवर्तनशील और अप्रत्याशित हो जाएगा। जैसे.जैसे भविष्य में गर्मी बढ़ेगी और बर्फ घटेगी पानी के बहने के बारे में विश्वसनीय अनुमान लगाने में कमी आएगी, यह जल संसाधनों की मात्रा और बारिश की मात्रा पर निर्भर हो जाएगा। इस अध्ययन की अगुवाई नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च (एनसीएआर) ने की है। प्रमुख अध्ययनकर्ता और एनसीएआर के वैज्ञानिक विल विडर ने कहा बर्फके पिघलने और प्रवाह का अनुमान लगाने के लिए चार से छह महीने का मुख्य समय होने के बजाय जल प्रबंधक हर एक वर्षा की घटना पर निर्भर होंगे। बर्फ की अधिकता वाले क्षेत्रों में जल प्रबंधन प्रणाली बर्फके पिघलने की गति पर आधारित होती है और इस तरह के पूर्वानुमान का अधिकांश भाग जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह गिरावट सदी के अंत में इतनी स्पष्ट हो जाएगी कि अमेरिकी रॉकी पर्वत के कुछ हिस्सों में औसत सर्दियों के अंत में बर्फमें जमे पानी की मात्रा लगभग 80 फीसदी तक कम हो सकती है।

अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि बर्फके तेजी से पिघलने और धारा प्रवाह में बदलाव से पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी प्रभाव पड़ने के आसार हैं, खासकर उन पर जो बर्फसे निकले पानी पर निर्भर करते हैं। हालांकि ये बदलाव पूरे क्षेत्रों में एक समान नहीं होंगे, बिना बर्फवाले दिनों की संख्या बढ़ेगी और लंबे समय तक बढ़ते मौसम, जल संसाधनों पर दबाव डालेंगे, कई क्षेत्रों में मिट्टी सूख जाएगी और आग का खतरा बढ़ जाएगा। अध्ययन में कहा गया है कि परिदृश्य एसएसपी 3-7.0 के मुताबिक ग्रीनहाउस गैसों की तीव्र उत्सर्जन दर पर जारी है। वीडर ने कहा कि यदि लोग सफलतापूर्वक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हैं तो बर्फ के तेजी से पिघलने और पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे गंभीर प्रभावों से बचा जा सकता है।

उन्होंने हाल ही में बनाए गए सिमुलेशन के डेटाबेस पर ध्यान आकर्षित किया, जिसे सीईएसएम2 लार्ज एनसेम्बल के रूप में जाना जाता है। पिछली अवधि 1940 से 1969 की तुलना में भविष्य की अवधि 2070 से 2099 से की गई। ये सिमुलेशन दक्षिण कोरिया के बुसान में बेसिक साइंस सुपर कंप्यूटर संस्थान में एलेफ सुपर कंप्यूटर पर चलाए गए थे। परिणाम बताते हैं कि 2100 तक दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पानी के प्रवाह के समय और सीमा में व्यापक बदलाव होगा। अधिक ग्रीनहाउस गैस मानकर उत्तरी गोलार्ध में औसतन लगभग 45 बिना बर्फ के दिन होंगे। उत्सर्जन सबसे बड़ी वृद्धि मध्य अक्षांशों में होगी जो अपेक्षाकृत गर्म और उच्च अक्षांश वाले समुद्री क्षेत्र हैं जो समुद्री बर्फमें परिवर्तन से प्रभावित होते हैं।

सभी किसान भाईयो और देशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव की
हार्दिक शुभकामनाये

NIRMAL ®
SEEDS

निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड ,पाचोरा महाराष्ट्र

सभी किसान भाईयो और देशवासियों को

स्वतंत्रता दिवस
एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव
की हार्दिक शुभकामनाये

Pareek Pesticides
101, Block-A Radhakrishna Complex 10/1 Manoramaganj,
Geeta Bhawan Chouraha A.B. Road Indore.
E-mail : sales@pareekgroup.com

सभी किसान भाईयो और देशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस
एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव
की हार्दिक शुभकामनाये

Anil Kumar Gupta

Western agri Seeds Ltd , Gandhinagar Gujarat

बीज भण्डार™
जैन एग्रो एजेंसी
बीज भंडार जैन एग्रो एजेंसी परिवार की और से स्वतंत्रता दिवस
एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव की किसान भाईयो एवं
क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
हेड ऑफिस : जैन एग्रों एजेन्सी, नूतन नगर खरगोन (म.प्र.) +91 78794 28271

बीज भण्डार™
जैन एग्रो एजेंसी
स्वतंत्रता दिवस
एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव की
किसान भाईयो एवं क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
सुनील हम्मड
मंडी प्रांगण आईजी एग्रो के पास बस स्टैंड कुक्षी 79748 81378

बीज भण्डार™
जैन एग्रो एजेंसी
स्वतंत्रता दिवस
एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव की
किसान भाईयो एवं क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
महिपाल ठाकुर
शॉप न. 3 भवानी माता मंदिर गेट के पास पंधाना रोड खंडवा 88898 43645

बीज भण्डार™
जैन एग्रो एजेंसी
स्वतंत्रता दिवस
एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव की
किसान भाईयो एवं क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
अंकित पाटीदार
वर्धमान स्कवायर बड़वाह 97536-63750

ईश्वेद
We mean, towards Green
सभी किसान भाईयो और देशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव
की हार्दिक शुभकामनाये
15TH AUGUST
INDIA
INDEPENDENCE
DAY
श्री संजय जी वायाळ
(CMD IshVed Group)
संकेतस्थळ : www.ishved.com ऑनलाईन उत्पादन खरेदीसाठी : www.ishvedmart.com

सभी किसान भाईयो और देशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस
एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव
की हार्दिक शुभकामनाये
VNR Seeds Pvt LTD, Raipur

बीज भण्डार™
जैन एग्रो एजेंसी
स्वतंत्रता दिवस
एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव की
किसान भाईयो एवं क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
कमलेश पाटीदार
अम्बेडकर चौराहा, मंडलेश्वर (म.प्र.) मोबा. 98268 41797

बीज भण्डार™
जैन एग्रो एजेंसी
स्वतंत्रता दिवस
एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव की
किसान भाईयो एवं क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
कमल कोशल
121, देवधर कॉम्प्लेक्स श्रीराम कृषि केंद्र के सामने इंदौर 88398-84302

बीज भण्डार™
जैन एग्रो एजेंसी
स्वतंत्रता दिवस
एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव की
किसान भाईयो एवं क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
धर्मेन्द्र गित्रारे
ब्लॉक ए-32, बस स्टैंड, खरगोन (म.प्र.) 97531 61205

बीज भण्डार™
जैन एग्रो एजेंसी
स्वतंत्रता दिवस
एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव की
किसान भाईयो एवं क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
मोहन परमार
श्री कृष्णा चौक, राजपुर रोड अंजड़ 94074 74208

बीज भण्डार™
जैन एग्रो एजेंसी
स्वतंत्रता दिवस
एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव की
किसान भाईयो एवं क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
रोहित जैन
शॉप न. 283 गौर तिराहा समाधी रोड़, जबलपुर 79879 74868

बीज भण्डार™
जैन एग्रो एजेंसी
स्वतंत्रता दिवस
एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव की
किसान भाईयो एवं क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
धर्मेन्द्र परमार
(राजपूत)
महालक्ष्मी कॉम्प्लेक्स पलसूद रोड़, SBI बैंक के पास राजपुर, 97550 75037

स्वतंत्रता दिवस
एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव की
किसान भाईयो एवं क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
रोहित कुशवाह
छोटा नाका इंदौर रोड़ कसरावद 97538 81107

आज़ादी का
अमृत महोत्सव
स्वतंत्रता दिवस
एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव की
किसान भाईयो एवं क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
गोलू सिंह सोलंकी
जैन हॉस्पीटल के पास ओल्ड AB रोड धामनोद 93283-21745

स्वतंत्रता दिवस
एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव की
किसान भाईयो एवं क्षेत्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
नितेश परमार
शॉप न 08 जनपद पंचायत कॉम्प्लेक्स, पुलिस थाने के
सामने इंदौर रोड़, मनावर 80853 83333

पीएम ने एनटीपीसी की 5200 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास

भारत की प्रगति को नई गति देगा पावर सेक्टरः पीएम मोदी

हलधर किसान। पीएम मोदी ने गत दिनों उज्वल भारत उज्वल भविष्य.पावर 2047 के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विद्युत क्षेत्र के लिए पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना के शुभारंभ के साथ ही 5200 करोड़ रुपये से अधिक की एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश में लगभग 1 लाख 70 हज़ार मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है। पूरे देश को जोड़ने के लिए लगभग 1 लाख 70 हजार सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई गई हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि समय के साथ हमारी राजनीति में एक गंभीर विकार आता गया है। राजनीति में जनता को सच बताने का साहस होना चाहिए, लेकिन हम देखतें हैं कि कुछ राज्यों में इससे बचने की कोशिश होती है। ये रणनीति तात्कालिक रूप से अच्छी राजनीति लग सकती है। लेकिन ये आज के सचए आज की चुनौतियों, अपने बच्चों के लिएए अपनी भावी पीढ़ियों के लिए टालने जैसा है।

राज्यों पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश को ये जानकर हैरानी होगी कि अलग.अलग राज्यों का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। ये पैसा उन्हें पावर जेनरेशन कंपनियों को देना है। पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों का अनेक सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों पर भी 60 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। अलग.अलग राज्यों में बिजली पर सब्सिडी का जो कमिटमेंट किया गया है, वो पैसा भी इन कंपनियों को समय पर पूरा नहीं मिल पाता। ये बकाया भी 75 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक का है। यानि बिजली बनाने से लेकर घर.घर पहुंचाने तक का जिम्मा जिनका हैए उनका लगभग ढाई लाख करोड़ रुपए फंसा हुआ है। जिन राज्यों के बकाया हैंए मेरा उनसे आग्रह है कि वे जितना जल्दी संभव हो सके सब क्लीयर करें। साथ ही उन कारणों पर भी ईमानदारी से विचार करें कि जब देशवासी ईमानदारी से अपना बिजली का बिल चुकाते हैंए तब भी कुछ राज्यों का बार.बार बकाया क्यों रहता है।

बिजली के बिना जीवन की कोई कल्पना नहीं

पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज के समय में बिजली के बिना जीवन की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। मेरे लिए बहुत संतोष का विषय है कि बीते वर्षों में हमने ऊर्जा के क्षेत्र में पिछली बहुत सी कमियों को दूर कर पॉवर सेक्टर को मजबूती दी है। पीएम ने आगे कहा कि आपको याद होगी कि आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18 हजार गांवों तक बिजली नहीं पहुंच सकी थी। आज के नए भारत में गांवों गांवों में लोग बिजली का बिजली का उत्पादन कर सकेंए इस दिशा में काम हो रहा है।

अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देगा पावर सेक्टर

पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी सेक्टर की मजबूती मेंम वक्रिपदह ठनेपदमे के लिए भी जरूरी है और उतनी ही अहम है।

पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि लद्दाख और गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन के दो बड़े प्रोजेक्ट पर आज से काम शुरु हो रहा है। लद्दाख में लग रहा प्लांट देश में गाड़ियों के लिए ग्रीन हाईड्रोजन का उत्पादन करेगा। ये देश का पहला प्रोजेक्ट होगा, जो ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ट्रांसपोर्ट के कमर्शियल इस्तेमाल को संभव बनाएगा। 8 साल पहले हमने देश के पावर सेक्टर के हर अंग को ट्रांसफॉर्म करने का बीड़ा उठाया। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए चार अलग.अलग दिशाओं में एक साथ काम किया गया। जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कनेक्शन पर जोर दिया गया। पीएम ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश में लगभग 1 लाख 70 हज़ार मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है।

आज हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे

पीएम मोदी ने कहा कि हमने आजादी के 75 साल पूरे होने तक 175 गीगावॉट रीन्युएबल एनर्जी कैपेसिटी तैयार करने का संकल्प लिया था। आज हम इस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। अभी तक गैर जीवाश्म स्रोत से लगभग 170 गीगावॉट कैपेसिटी स्थापित की जा चुकी है। इसी कड़ी में आज दो और बड़े सोलर प्लांट्स देश को मिले हैं। तेलंगाना और केरला में बने ये प्लांट्स देश के पहले और दूसरे नंबर के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हैं। सरकार का जोर बिजली का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही बिजली की बचत करने पर भी है। बिजली बचाना यानि भविष्य सजाना है। पीएम कुसुम योजना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हम किसानों को सोलर पंप की सुविधा दे रहे हैं, खेतों के किनारे सोलर पैनल लगाने में मदद कर रहे हैं। आज स्थापित सौर क्षमता के मामले में भारतए दुनिया के टॉप 4.5 देशों में है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में से अनेक आज भारत में हैं।

राष्ट्रीय सोलर रूफटॉप पोर्टल का किया शुभारंभ

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सौलर रूफटॉप पोर्टल का भी शुभारंभ किया। बिजली मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम, पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। जिसका उद्देश्य डिस्कॉम कंपनियों और बिजली विभागों की परिचालन क्षमता तथा वित्तीय स्थिति में सुधार करना है। वित्त वर्ष 2021.22 से वित्त वर्ष 2025.26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ इस योजना का उद्देश्य बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए डिस्कॉम कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ताकि उपभोक्ता के लिए आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार हो सके।

कई राज्यों को मिलेगा लाभ

पीएम मोदी ने तेलंगाना के 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल के 92 मेगावाट कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसके अलाव पीएम ने राजस्थान में 735 मेगावाट की नोख सौर परियोजना, लेह में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना और गुजरात में कावास प्राकृतिक गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला रखी। रामागुंडम परियोजना भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना हैए जिसमें 4.5 लाख मेड इन इंडिया सोलर पीवी मॉड्यूल हैं। कायमकुलम परियोजना दूसरी सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना है, जिसमें पानी पर तैरते 3 लाख मेड इन इंडिया सोलर पीवी पैनल शामिल हैं।

सेब पर भी महंगाई की मार, कार्टन और पैकेजिंग मटेरियल दामों पर 10 से 15 फीसदी बढ़े, सेब बागवान नाराज

हलधर किसान। सेब उत्पादन में दूसरे स्थान में रहने वाले हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सेब सीजन शुरू होने जा रहा है। प्रदेश में इस बार सेब की बंपर फसल होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इससे जहां सेब बागवान खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ सेब के कार्टन और पैकेजिंग मेटेरियल के दामों में हुई 10 से 15 फीसदी की बढ़ोतरी से सेब बागवान नाराज हैं और आंदोलन भी किए जा रहे है।

हिमाचल प्रदेश में 2 लाख से अधिक सेब बागवान सीधे तौर पर सेब बागवानी से जुड़े हुए हैं और प्रदेश में हर साल लगभग 4 करोड़ सेब की पेटियों के उत्पादन से 5 हजार करोड़ रुपए का कारोबार होता है। ऐसे में सेब के कार्टन और अन्य पैकेजिंग मेटेरियल में हुई बढ़ोतरी से नाराज सेब बागवान सड़कों पर उतर चुके है। आप और कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। बागवानों का कहना है कि सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य को साढ़े 9 रुपए से बढ़ाकर केवल साढ़े 10 रुपए किया जाना भी है।

बागवानों का कहना है कि अब सेब की एक पेटी की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 300 से 350 रुपए तक पहुंच गया है। हिमाचल में सेब बागवानों के लिए कार्टन के दाम तय करने का काम सरकारी संस्था बागवानी उत्पाद विपणन निगम की ओर किया जाता है।

निगम की ओर से कार्टन के लिए तीन कंपनियों को चयनित किया गया है। जिनके दाम पिछले वर्ष के मुकाबले में 10 से 15 रुपए अधिक हैं। यदि पिछले वर्ष से तुलना करें तो 20 किलोग्राम की सेब की पेटी के कार्टन के दाम पिछले वर्ष 68.67 रुपए थे जो इस साल 75.65 रुपए पहुंच गया है। वहीं सफेद व भूरे कार्टन के दाम 64.51 से 71.71 रुपएए भूरे रंग के डबल वर्जन कार्टन के दाम 60.13 से 67.71 रुपए, भूरे रंग के सिंगल वर्जन कार्टन 58.83 ये 66.78 रुपए, सफेद कार्टन 10 किलोग्राम 46.62 से 52.40 और सफेद व भूरे रंग के कार्टन का दाम 43.72 से 50.43 रुपए हो गया है। इसके अलावा सेब की पेटियों में प्रयोग होने वाली ट्रे के दाम भी 5 रुपए से 8 रुपए प्रति ट्रे हो गया है। हिमाचल सरकार की ओर से दलील दी गई कि पैकेजिंग मेटेरियल के दामों में बढ़ोतरी जीएसटी की दरों में हुई वृद्धि से देखने को मिली है। हालांकि सरकार ने पैकेजिंग मेटेरियल पर बढ़ी हुई 6 प्रतिशत की दर को सरकार के खाते से भरने की राहत बागवानों को देने की घोषणा की है, बावजूद इसके बागवान खुश नहीं हैं और वे जीएसटी की दरों के अलावा भी बढ़ी दरों को कम करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं।

संयुक्त किसान मंच ने सरकार से एक देश एक विधान की नीति पर काम करते हुए कश्मीर की तर्ज पर मंडी मध्यस्थता योजना के तहत तीन श्रेणियों के लिए 60 रुपए, बी के लिए 44 और सी के लिए 24 रुपए प्रति किलोग्राम के आधार पर सेब की खरीद की मांग भी उठाई है।

किसानों के हित में योजनाओं की समीक्षा का क्रम रहेगा जारीः मुख्यमंत्री श्री चौहान

हलधर किसान। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य शासन के मूंग खरीदी सहित अन्य किसान हितैषी निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया। प्रतिनिधि मंड ल ने किसानों के कल्याण के संबंध में सुझाव-पत्र सौंपा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भविष्य में भी प्राथमिकता के साथ किसान.कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि प्रदेश के किसानों के हित में संचालित योजनाओं की सतत समीक्षा का क्रम भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान से भेंट करने वालों में भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष कमल सिंह आंजना, क्षेत्र संगठन मंत्री महेश चौधरी, प्रदेश इकाई के महामंत्री चंद्रकांत गौर, प्रांत संगठन मंत्री मनीष शर्मा और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने की घोषणा

अगले 1 साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की कीमतों के होगी बराबर

हलधर किसान। कार और बाइक चलाने वालों के लिए राहतभरी खबर है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि देश में अगले 1 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतें पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की कीमतों के बराबर हो जाएगी। नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंफ्रास्ट्र. र में ऐसा बदलाव लाने की तैयारी की जा रही है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की लागत में कमी आएगी और ईवी की कीमतें पेट्रोल गाड़ियों की कीमतों के बराबर हो जाएंगी।

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि प्रोद्योगिकी और हरित ईंधन में तेजी से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत कम हो जाएगी। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल की लागत को कम करने पर जोर डाल रही है और इसी पर काम कर रही है।

प्रदूषण का स्तर होगा कम

नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये बयान दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2022.23 के लिए अनुदान की मांगों पर लोकसभा में जवाब मांगा गया, जिस पर नितिन गडकरी ने जवाब देते हुए कहा कि अगले 1 साल में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल गाड़ियों की कीमतों के बराबर कर दी जाएगी।

हाइड्रोजन टेक्निक बनाने का आग्रह

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसदों से हाइड्रोजन तकनीकी अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने सांसदों से कहा कि अपने. अपने क्षेत्र में सीवेज के पानी को हरित हाइड्रोजन बनाने की पहल करें। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जल्द हाइड्रोजन सबसे सस्ता ईधन होगा। लिथिमय आयन बैटरी की कीमत में तेजी से कमी आ रही है। हम जिंक. आयन, एल्यूमीनियम. आयन, सोडियम. आयन बैटरी को विकसित कर रहे हैं।

खर्च में कितना आएगा बड़ा अंतर

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार इसका फायदा यह होगा यदि आप आज पेट्रोल पर 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने में यह लागत घटकर 10 रुपये आ जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से चलने पर महज 1 रुपये प्रति किमी से भी कम का खर्च आएगा, जबकि पेट्रोल पर चलने वाली कार का खर्च 5.7 रुपये प्रति किमी आता है, अब वहां कंपनी निर्माता भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर काम कर रही है।

गौमूत्र खरीदने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़, सीएम बघेल बने पहले विक्रेता

हलधर किसान। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया, जहां 2 रुपए किलो गोबर खरीदकर अब 4 रुपए लीटर गोमूत्र खरीद रहा है। खेती किसानी से जुड़े प्रदेश के पारम्परिक त्यौहार हरेली पर्व के मौके पर राजधानी रायपुर स्थित सीएम हाउस में सीएम भूपेश बघेल ने गौ माता की पूजा-अर्चना कर गौमूत्र खरीदी योजना का आगाज किया। मुख्यमंत्री ने राज्य की जैविक खाद बनाने वाली 7442 महिला स्वयं सहायता समूहों को 17 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी वितरित की।

इस दौरान सीएम हाउस में आयोजित कई पारम्परिक कार्यक्रमों के दौरान सीएम भूपेश बघेल भी संस्कृति के रंग में रंगे नजर आये। अपनी तरह की अनूठी योजना गौमूत्र खरीदी की शुरुआत करते हुए सीएम ने चंदखुरी की निधि स्व सहायता समूह की महिलाओं से गौमूत्र बेचा, इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के सबसे पहले गौमूत्र विक्रेता बनकर इतिहास रच दिया। सीएम भूपेश बघेल 5 लीटर गौमूत्र का विक्रय करके 20 रूपए अर्जित किये और विक्रय रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया।

सीएम ने गौमाता को अपने हाथो से चारा खिलाकर उनकी पूजा अर्चना की। इससे पहल उन्होंने ट्वीटर पर लिखा कि हरेली के शुभ अवसर पर हमने आज से 2 वर्ष पूर्व 'गोधन न्याय योजना' की शुरुआत की थी, जिसने देश को रास्ता दिखाया, पशुपालकों को सशक्त बनाया। आज हरेली के शुभ अवसर पर हम गौ.मूत्र खरीदी की भी शुरुआत कर रहे हैं। 4 रुपए लीटर की दर से गौ-मूत्र की खरीदी की जाएगी।

श्री गोस्वामी का कार्यकाल सराहनीय और अनुकरणीय रहा है: उप संचालक चौहान

कृषि आदान विक्रेता संघ ने समारोहपूर्वक दी विदाई

खरगोन, (हलधर किसान)। कृषि विभाग में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नरेंद्र गोस्वामी की सेवानिवृत्ति पर कृषि आदान वि क्रेता संघ ने विदाई समारोह आयोजित किया। राधाकुंज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश महामंत्री कृषि आदान विक्रेता संघ विनोद जैन, जिलाध्यक्ष नरेंद्र चावला सहित अन्य पदाधिकारियों ने श्री गोस्वामी का शॉल.श्रीफल एवं अभिनन्दन पत्र भेंटकर उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद नई जिम्मेदारियों के लिये उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

उपसंचालक कृषि एमएल चौहान ने कहा की श्री गोस्वामी का कार्यकाल सराहनीय और अनुकरणीय रहा है, यह उनके सरल, काम के प्रति ईमानदारी वाला स्वभाव है जो आज उनका सम्मान हो रहा है। सेवानिवृत्ति प्रदेश महामंत्री जैन ने कहा करीब 32 साल से श्री गोस्वामी जिले में पदस्थ है, इतने लंबे समय तक किसानों और व्यापारियों के बीच सामंजस्य ओर भरोसा बनाये रखना किसी भी अधिकारी के लिये किसी चुनौती से कम नही होता, लेकिन गोस्वामी का इतना लंबा कार्यकाल बिना किसी विवाद के समाप्त होने जा रहा है यह उनकी कार्यकुशलता ओर कर्तव्य के प्रति ईमानदारी को दर्शाता है।

कार्यक्रम को प्रितेश अग्रवाल, राजेन्द्र पाटीदार, उपसंचालक उद्यानिकी मोहन मुजाल्दे, एसएडीओ गिरधारी भावर ने भी संबोधित करते हुए कहा की श्री गोस्वामी की कार्यशैली सबसे अलग थी जो हमेशा याद रहेगी। अपने सम्मान पर भावुक होते हुए श्री गोस्वामी ने कहा कि सरकार की ओर से भले ही मुझे विदाई मिल गई हो लेकिन मेरी आत्मा आज भी खरगोन क्षेत्र के किसानों में बसी हुई हैं उन्हें जब भी मेरी आवश्यकता पडेगी मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। इस दौरान कृषि अधिकारी प्रकाश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कृषि आदान विक्रेता मौजूद रहे।

स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्यान्न उत्पादन करना ही वैज्ञानिक तकनीक का मुख्य लक्ष्य: कृषि मंत्री श्री पटेल

हलधर किसान। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में 'फसल सुधार के लिये जीन एडिटिंग' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा से वर्चुअली जुड़कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा किसी भी वैज्ञानिक तकनीक का मुख्य लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण और स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्यान्न उत्पादन होना चाहिये।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्म.निर्भर भारत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आत्म.निर्भर वैज्ञानिकों द्वारा फसलों की नवीन किस्मों को तैयार करने के लिए नवीन तकनीकों का विकास किया जा रहा है। फसल सुधार के लिये जीन एडिटिंग एक प्रभावशाली तकनीक है। जीन एडिटिंग से जलवायु परिवर्तन, फसलों में आमतौर पर होने वाली बीमारियों और कीट.प्रकोप पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने के प्रयास भी होने चाहिये। मंत्री श्री पटेल ने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि निश्चित ही इस कार्यशाला में किये गये चिंतन और मंथन से प्राप्त होने वाले निष्कर्षों का लाभ कृषि और किसानों को मिलेगा। कार्यशाला में वैज्ञानिकों ने अपने विचार व्यक्त किये।

कार्यशाला में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति प्रो. एसके. राव, रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झाँसी के कुलपति डॉ. एसके चतुर्वेदी, बॉयो टेक्नालॉजी सेंटर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डायरेक्टर प्रो. शरद तिवारी, बॉयोटेक कंसोर्टियम इण्डिया लिमिटेड की चीफ जनरल मैनेजर डॉ. विभा आहूजा, नेशनल इंस्टीट्यूट फार प्लांट बॉयो टेक्नालॉजी के पूर्व संचालक डॉ. एनके सिंह, फेडरेशन ऑफसीड इण्डस्ट्री ऑफइण्डिया के डायरेक्टर जनरल श्री राम कौंडिन्य सहित कई अन्य वैज्ञानिक और शोधार्थी मौजूद थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व प्रधान संपादक विवेक जैन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, बलवंत मार्केट, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित व प्रकाशित। Titel Code. MPHIN/2022/37675
, मोबा. नं. 98262 25525, 94254 89337, (समस्य प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा) । प्रधान संपादक - विवेक जैन, सलाहकार संपादक - पंकज यादव